भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखति प्रश्न संख्या : 812
सोमवार, 27 जुलाई, 2026 (5 श्रावण 1948 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान योजना की स्थापना हेतु आवंटित कुल धनराशि

812. श्री आर. गिरिराजनः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि उड़ान योजना के अंतर्गत घोषित अनेक विमानपत्तनों का कार्य अभी भी अधूरा है तथा अनेक पूर्ण हो चुके उड़ान विमानपत्तनों पर अभी तक हवाई सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में पूर्ण एवं परिचालित उड़ान विमानपत्तनों की कुल संख्या कितनी है तथा उनकी राज्य-वार सूची क्या है;

(ग) देश में घोषित किन्तु अभी भी अपूर्ण तथा गैर-परिचालित उड़ान विमानपत्तनों की राज्य-वार सूची क्या है;

(घ) देश में उड़ान विमानपत्तनों की स्थापना के लिए विमानपत्तन-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं; और

(ङ) वेल्लोर विमानपत्तन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उड़ान विमानपत्तनों के लंबित कार्य कब तक पूर्ण किए जाने की संभावना है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-'उड़ान') के तहत, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 17 हेलीपोर्टों और 2 वॉटर एयरोड्रोमों सहित कुल 95 हवाईअड्डों को विकसित और प्रचालनरत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, परिचालन और एयरलाइन-संबंधी कारणों से 14 हवाईअड्डों पर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ान परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित हैं। ये हवाईअड्डे तेजपुर, कांडला, दतिया, गोंदिया, पठानकोट, जैसलमेर, पाक्योंग, कुशीनगर, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती, मुरादाबाद और कूच बिहार हैं।

इस योजना के तहत हवाईअड्डों/हेलीपोर्टों/वॉटर एयरोड्रोमों के पुनरुद्धार और विकास के लिए, अभी तक योजना के पहले चरण में 4500 करोड़ रुपये और दूसरे चरण में 1000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लक्षित करते हुए, 'उड़ान' योजना का अगला चरण दिनांक 04.07.2026 को शुरू किया गया है। इस योजना को वित्त

वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक 28,840 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें एयरोड्रोम विकास के लिए 12,159 करोड़ रुपये और पर्वतीय, उत्तर-पूर्वी एवं आकांक्षी (एचआईएनईआर) राज्यों/जिलों में 200 हेलीपोर्टों के विकास के लिए 3,661 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ङ): वेल्लोर हवाईअड्डे पर विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में, बीसीएएस सुरक्षा क्लीयरेंस और डीजीसीए लाइसेंसिंग से संबंधित प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, हवाईअड्डों पर विकास कार्यों के पूर्ण होने की समय-सीमा भूमि अधिग्रहण, वैधानिक मंजूरियों और वित्तीय समापन जैसे कारकों पर निर्भर करती है।

*****